IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विकसित भारत की परिसंकल्पना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्त्व एवं चुनौतियाँ : एक अध्ययन

– अंजु चौधरी

एम.ए. (अर्थशास्त्र), पीएच.डी., पटना विश्वविद्यालय

सार : इेजतंबजद्धरू खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जो खेतों में खराब होने वाली और जलवायु निभर फसलों को कुशल लागत के साथ ऐसे उत्पादों में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती हैं जिन्हें लम्बे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति उपभोक्ताओं में बढते जागरूकता के कारण सुरक्षित और पौष्टिक प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की माँग बढने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना 1988 में की गई थी। इस क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए सरकार द्वारा कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ– प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना ;च्डज्ञैल्द्ध, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ;च्स्प्द्ध योजना, एक जिला एक उत्पाद ;व्क्व्द्ध, मेक इन इंडिया तथा लोकल फॅार वोकल आदि कार्यान्वित की गई। साथ ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;छ।ठ।त्क्द्ध, द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता और विकासात्मक सहयोग प्रदान करने के कारण खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण संभव हो पा रहा है। कम लागत वाले भंडारण, विपणन व वितरण में आसानी तथा ग्रामीण व शहरी इलाकों में नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। भारत की उच्च आर्थिक विकास और बढती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

कुजीशब्द ;ज्ञमलूवतकद्धः 1. खाद्य–प्रसंस्करण, 2. उत्पाद, 3 . खाद्य–पदार्थ, 4 दृ निवेश, 5 दृ अर्थव्यवस्था

परिचय:

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समग्र खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इसमें कच्चे कृषीय तथा पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए उपयुक्त, प्रसंस्कृत व मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र का उद्देश्य खाद्य उत्पादों को सुरक्षित तथा लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के साथ उनके स्वाद एवं पोषण मूल्य में वृद्धि करना है। इस क्षेत्र में बड़ी संभावना, विशाल बाजार के साथ कई भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में अपनी प्रत्यक्ष निवेश गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके द्वारा कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रमुख क्षेत्र प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों, मोजारेला पनीर, प्रसंस्कृत समुद्री उत्पाद, खाद्य तल, पेय पदार्थ तथा डेयरी उत्पाद हैं। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11ण्2 प्रतिशत हिस्सा रखने वाला भारत दूध, दाल तथा जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर, सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग[1] देश के कुल बाजार का 32 प्रतिशत हिस्सा है। यह भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से है तथा उत्पादन, खपत, निर्यात व अपेक्षित वृद्धि के मामले में पाँचवें स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत, निर्यात में 13 प्रतिशत तथा आद्योगिक निवेश में 6 प्रतिशत का योगदान है। इस अध्ययन के विश्लेषण मे द्वितीयक आँकड़ों को विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, विशेषांकों एवं रिपोर्टों तथा जर्नलों से संग्रह कर उपयोग किया गया है जिसमें इसका आर्थिक महत्त्व, सरकार द्वारा लागू की गयी योजनाएँ, इस क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियाँ तथा इसकी भविष्य की राहें का वर्णन किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आर्थिक महत्त्वः

जहा उच्चतर उत्पादकता जीवन्त कृषि का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है वहीं फसल कटाई की बेहतर व्यवस्था, बाद का रख रखाव, प्रसंस्करण अपशिष्ट में कमी तथा बाजार तक अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का पहुँचना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे इस उद्योग के आर्थिक महत्त्व[2] निम्नलिखित हैं –

[1] The Analyses are based on several volumes of Economic Survey, India and the relevant documents of the Government of India between the periods of 2008-24.

[2] Economic Survey 2021-22 (New Delhi: Ministry of Finance, GoI), pp. 255-258 and Economic Survey 2022-23 (New Delhi: Ministry of Finance, GoI), pp. 255-256.

1. सरकार द्वारा स्वचालित मार्ग के तहत इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। अप्रैल 2014 से सितम्बर 2022 तक की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 5ण्1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह देखा गया है।
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2019.20 के अनुसार देश के पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुल 18ण्33 लाख लोग संलग्न थे।
3. गैर–पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आज 51ण्11 लाख लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है ;छैब् 73वां दौर, 2015.16द्ध, जो गैर–पंजीकृत विनिर्माण उद्योग के रोजगार का 14ण्18 प्रतिशत है।
4. पिछले पाँच वर्षों में ;2020.21द्ध तक इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 8ण्3 प्रतिशत रही।
5. किसानों को उच्च उत्पादन से बेहतर प्राप्ति तथा जोखिम घट रहा है। उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्यों पर नए विविधता वाले उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं।
6. अर्थव्यवस्था को नए व्यवसाय के उत्पन्न होने तथा कार्यबल को रोजगार मिल रहा है।
7. भारत के बाजार का आकार बढ रहा है, बढती आय तथा बदलती जीवनशैली के साथ उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, संयंत्र निर्माताओं, खाद्य तकनिशियनों तथा सेवा दाताओं के लिए अविश्वसनीय अवसर पैदा हाते रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल तथा योजनाएँः

विकसित भारत के संकल्पना में इस उद्योग की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न निम्नलिखित याजनाएँ लागू करने की पहल की गई –

1. एकीकृत एवं पूर्णशीत श्रंखला, मूल्य योग एवं संरक्षण ;प्दजमहतंजमक ब्वसक बैंपदए टंसनम ।ककपजपवद दक च्तमेमतअंजपवदद्ध – यह योजना 2008 में स्वीकृत हुई थी जिसका उद्देश्य एकीकृत एवं पूर्णशीत श्रंखला, मूल्य योग एवं संरक्षण संबंधी सुविधाएँ निरंतरता के साथ प्रदान करना और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए खेत से लेकर उपभोक्ता के हांथों तक पहुँच सुनिश्चित करना था।
2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना ;च्डझैल्द्ध – यह योजना 2016.17 में शुरू की गई। इस केन्द्रिय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए आधुनिक अधिसंरचना के विकास के लिए छूट आधारित सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न संघटक आत है –
   2ण्1 मेगा फूड पार्क,
   2ण्2 वधशालाओं या बूचड़खानों का आधुनिकीकरण,
   2ण्3 तकनीकि उन्नयन,
   2.4 गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा प्रोत्साहक गतिविधियाँ
3. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेनटिव योजना ;च्स्प्द्ध – नवम्बर 2020 में सरकार द्वारा 14 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी शामिल किया गया। इसमें निर्यात के लिए समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों, मोजारेला पनीर तथा लघ उद्योगों द्वारा कार्बनिक उत्पाद आदि को शामिल किया गया। यह योजना ब्रांडिग एव विपणन विकास को भी सहयोग प्रदान करती है।
4. ऑपेरेशन ग्रीन्स – 2018.19 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य टमाटर, प्याज एवं आलू ;ज्व्द्ध के लिए समेकित मूल्यवर्द्धन श्रृंखला का विकास करना था जिसके पाँच प्रमुख लक्ष्य हैं –
   4.1 इसे बाजार से जोड़ना,
   4.2 इनके मूल्य का स्थिरीकरण,
   4.3 आधारभूत संरचना का विकास द्वारा तैयार फसल के क्षय को कम करना,
   4.4 खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास और
   4.5 माँग एवं आपूर्ति संबंधी आँकड़ों की उपलब्धि के लिए मार्केट इंटेलिजेन्स नेटवर्क का विकास।
5. प्रधान मंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राइजेज ;च्ब्.थ्डम्द्ध – आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020.21 में प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य एक जिला एक उत्पाद ;क्व्व्द्ध को प्रोत्साहन देना है। आगामी पाँच वर्षों के लिए लागू इस योजना के माध्यम से आगतों की वसूली, आम सेवाओं एवं विपणन व्यवस्था के माध्यम से अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना है। इसके अंतर्गत राज्यों को प्रति जिला एक उत्पाद का चयन तथा उसके कच्चे माल के क्षेत्रों का ध्यान रखना होता है। नीति आयोग ने देश के ऐसे 112 आकांक्षी जिलों की पहचान की है जिसमें लघु वनोपज ;डपदवत थ्वतमेज च्तवकनबजेद्ध जैसे बाँस, लाख, तेन्दु के पत्ते आदि को शामिल किया गया है।
6. खाद्य प्रसंस्करण कोष की स्थापना – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;छ।ठ।त्क्द्ध के साथ 2000 करोड़ रू0 का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष की स्थापना की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँः

कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद भी किसानों का बड़ा वर्ग ना तो खाद्य उत्पादों की प्रसंस्करण तकनीक से परिचित है और ना ही उसे बाजार मिल

पाता है। किसानो के पास अपना कौशल तो है लेकिन उस कौशल को तकनीक से जोड़ने के साधन उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ है –

1. काल्ड चैन तथा भंडारण की कमी – अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तथा परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण फसलें शीघ्र खराब हा जाती हैं। इससे ना केवल भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि किसानों की आय पर भी बुरा असर पड़ता है।
2. खंडित आपूर्ति श्रंखला – भारत में आपूर्ति श्रंखला अत्यधिक खंडित होने के कारण बढी हुई लागत के साथ खाद्य अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। खराब सड़क और रेल बुनियादी ढाँचे के कारण परिवहन में देरी से नुकसान होता है।
3. जटिल नियम – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नियमों, लाईसेंस और परमिट के एक जटिल जाल के अधीन है जिसका समाधान करना व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है।
4. नियमों का असंगत प्रवर्तन – अनुचित प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। दूषित या मिलावटी खाद्य उत्पाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ ही क्षेत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं।
5. अनुसंधान और विकास – इसमें सीमित निवश नवाचार और नए मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का अनुसंधान और विकास व्यय का जी.डी.पी. अनुपात 0ण्7 प्रतिशत है जो कि विश्व औसत 1ण्8 प्रतिशत से काफी नीचे है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की आगे की राहें:

उपर्युक्त चुनातियों से निपटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष तकनीकि नवाचार अपनाए जा सकते है –

1. स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब – इन्टरनेट ऑफ थिंग्स ;प्वज्द्ध, कृत्रिम मेधा ; ।प्द्ध और ब्लॉक चैन जैसी उन्नत तकनीकों से लैस स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब की स्थापना की जानी चाहिए। ये केन्द्र गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता तथा दक्षता सुनिश्चित करते हुए खेत से लेकर थाली तक सम्पूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी कर सकते है।
2. न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन – विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यात्मक तथा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला का विकास करना चाहिए। इनमें भारतीय आबादी में प्रचलित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों प्रोबायोटिक्स तथा बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं।
3. शून्य अपशिष्ट प्रसंस्करण – इस तकनीक को अपना कर कच्चे माल के प्रत्येक भाग का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए खाद्य अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करना या पशुचारा और जैव–प्लास्टिक जैसे नए उत्पाद बनाने हेतु खाद्य उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है।
4. समुदाय आधारित प्रसंस्करण केन्द्र – ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित कर किसानों के लिए उनकी उपज को संसाधित करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने तथा ग्रामीण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के केन्द्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

विकसित भारत की परिसंकल्पना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विशेष महत्त्व है। यह कृषि क्षेत्र के विकास के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में भी सहायक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र तथा बाजार में बड़े बदलाव करने हांगे। परम्परागत कृषि को आधुनिक कृषि व्यवसाय में बदलने की आवश्यकता है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का व्यापक योगदान हो सकता है। वर्तमान में बढती हुई आबादी, बदलती जीवनशैली, बढती डिस्पोजेबल आय, शहरीकरण एवं पैकेज्ड व सेल्फ कुक्ड खाद्य उत्पादों की बढती माँग, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बढती जागरूकता के कारण खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11ण्2 प्रतिशत हिस्सा रखने वाला भारत दूध, दाल तथा जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर, सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत में खाद्य तथा किराना बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है। विशाल बाजार अवसरों के साथ भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विपुल संभावनाएँ हैं। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निमार्ण किया जा रहा है। इस योजना के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है तथा कृषि अधिशेष कच्चे माल की बर्बादी भी कम हुई है। इसके लिए हाल ही में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसे अभियान चलाए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन, पैकेजिंग, वितरण तथा मूल्य आदि की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने के लिए तकनीकि नवाचार तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्कता है। बाजार मं सामूहिक ब्रांड प्रमोशन जैसे उपकरण विकसित करने की भी आवश्यकता है ताकि ऋण, सक्षम वातावरण, विपणन और विस्तार सेवा युक्त बाजार का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उभरता हुआ क्षेत्र है जिसको सरकारी तथा तकनीकि नवाचार की सहायता से और अधिक युक्ति संगत बनाया जा सकता है।

संदर्भ व संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. The Analyses are based on several volumes of Economic Survey, India and the relevant documents of the Government of India between the periods of 2008-24.
2. Economic Survey 2021-22 (New Delhi: Ministry of Finance, GoI), pp. 255-258 and Economic Survey 2022-23 (New Delhi: Ministry of Finance, GoI), pp. 255-256.
3. प्रियदर्शिनी, पी. और अभिलाष, पी. सी. ;2020द्ध। भारत में टिकाऊ कृषि की ओर बदलाव को सक्षम करने के लिए नीतिगत सिफारिशें।
4. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, डबळतूं भ्पसस म्कनबंजपवद ;प्दकपंद्ध च्अजण स्जकण्ए 2024.25ण चचण 135.138ण
5. योजना, जुलाई, 2024, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
6. www.mofpi.gov.in
7. www.indiabudget.gov.in

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation